

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक—प्र० / SBPDCL—03 / 2019

/ पटना, दिनांक—

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन भागलपुर, गया, बोधगया शहर (पूर्व वितरण फेंचाईजी क्षेत्र) एवं आरा में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 346.54 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चौबन लाख) रुपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 346.54 करोड़ रुपये का 60 प्रतिशत 207.924 करोड़ (दो सौ सात करोड़ बानवे लाख चालीस हजार) रुपये भारत सरकार द्वारा अनुदान, 10 प्रतिशत 34.654 करोड़ (चौंतीस करोड़ पैसठ लाख चालीस हजार) रुपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत 103.962 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ छियानवे लाख बीस हजार) रुपये वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं गारंटी। पावर सब-स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में साउथ बिहार पावर डिं० कं० लि० को 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के अन्तर्गत 65 शहरी क्षेत्रों में से 4 वितरण फेंचाईजी क्षेत्र छोड़ कर शेष 61 शहरी क्षेत्रों में वितरण एवं उप-संचरण संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग, सरकारी भवनों में सोलर पैनल का अधिष्ठापन एवं ए०टी० एण्ड सी० हानि में उत्तरोत्तर कमी करने हेतु नोडल एजेन्सी पी०एफ०सी० द्वारा 1042.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 1042.50 करोड़ रुपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी पी०एफ०सी० के माध्यम से अनुदान, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा (104.25 करोड़ रुपये) हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू-खण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से करने की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—2461 दिनांक—24.08.2015 द्वारा प्रदान की गई। पुनः विभागीय राज्यादेश संख्या—2466 दिनांक— 04.10.2018 द्वारा इस योजना के लिए 1093.92 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. पूर्व में वितरण फेंचाईजी क्षेत्र होने के कारण भागलपुर, गया एवं बोधगया शहर आई०पी०डी०एस० योजना के अंग नहीं थे। वर्तमान में यहाँ वितरण फेंचाईजी का एकरारनामा रद्द किया जा चुका है। आई०पी०डी०एस० योजना के कार्यान्वयन हेतु भागलपुर, गया, बोधगया एवं आरा शहर के लिए 409.71 करोड़ रुपये का डी०पी०आर० पी०एफ०सी० को समर्पित किया गया। उपलब्ध राशि के अनुरूप सिर्फ भागलपुर, गया एवं बोधगया शहर का 346.54 करोड़ रुपये की संशोधित डी०पी०आर० की स्वीकृति पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। इस योजना की स्वीकृति हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के द्वारा अनुरोध किया गया है।

3. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन भागलपुर, गया, बोधगया शहर (पूर्व वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र) एवं आरा में इटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 346.54 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चौवन लाख) रुपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 346.54 करोड़ रुपये का 60 प्रतिशत 207.924 करोड़ (दो सौ सात करोड़ बानवे लाख चालीस हजार) रुपये भारत सरकार द्वारा अनुदान 10 प्रतिशत 34.654 करोड़ (चौंतीस करोड़ पैसठ करोड़ (एक सौ तीन करोड़ छियानवे लाख बीस हजार) रुपये वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं गारंटी। पावर सब-स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में साउथ बिहार पावर डिं० कं० लि० को 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. उक्त राशि माँग सं०-१०, बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-०५ संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-१९०-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, माँग सं०-१०, उपशीर्ष-०१०६ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-१०-४८०१०५१९००१०६ विषय शीर्ष ५४०१-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं अगले वित्तीय वर्ष में उपबंध राशि से विकलनीय होगा।
5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष ८४४८-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-१२०-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-००४७-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, व्यय शीर्ष-L४४४८००१२०००४७ एवं प्राप्तियाँ-८४४८००१२०००४७ में जमा की जाएगी।
6. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।
7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-३७५८ दिनांक-३१.०५.२०१७ के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-७३५५ दिनांक-०५.१०.२००७ के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/SBPDCL-०३/२०१९ के पृष्ठ संख्या-०९/टि० पर दिनांक-१८.०२.२०१९ को प्राप्त है।
10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/SBPDCL-०३/२०१९ पृष्ठ संख्या-१२/टि० पर दिनांक-२२.०२.२०१९ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— प्र० / SBPDCL-03 / 2019

/ पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि:—महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /—

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— प्र० / SBPDCL-03 / 2019 — ५५६ / पटना, दिनांक— २९/०२/२०१९

प्रतिलिपि:—वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिं/प्रबन्ध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार